

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-1717/2017

घेवरचन्द बंजारा

—अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर।
3. बीईईओ, जवाजा, जिला अजमेर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 22.08.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से दिनांक 31.12.2016 को सेवानिवृत्त हो चुका है। प्रत्यर्थी विभाग ने वेतन स्थरीकरण को त्रुटिपूर्ण मानते हुए अधिक वेतन देने की अवधि दिनांक 08.12.2011 से दिसम्बर, 2016 तक बताया है और अपीलार्थी से 43081/- रुपये की वसूली की है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.12.2016 को हुई थी, से 9 दिन पूर्व की अपीलार्थी से वसूली की गयी है। अधिक वेतन भुगतान किये जाने में अपीलार्थी की कोई गलती नहीं रही है। ऐसे में सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व वसूली किया जाना उचित नहीं है।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे यह कथन रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 में यह निर्धारित किया है कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय एवं सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व वसूली नहीं की जानी चाहिए।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी को अधिक वेतन भुगतान किये जाने में अपीलार्थी की कोई गलती नहीं रही है। इसके अलावा अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। अपीलार्थी से उसकी सेवानिवृत्ति से 9 दिन पूर्व की उससे वसूली की गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है :-

State of Punjab v Rafiq Masih 2015 (1) SCT 195

"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the

following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

- (i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).
- (ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.
- (iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.
- (iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.
- (v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

4. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से एवं ऐसे कर्मचारी से जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय शेष रहा हो तो उनसे वसूली किया जाना उचित नहीं है। अतः यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।
5. यह अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी से वसूल की गयी राशि 43081/- मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ अपीलार्थी को वापस लौटाई जाए। इस आदेश की पालना तीन माह में की जाए।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)